राज्य सरकार हर वर्ष ''प्रवासी राजस्थान सम्मान'' देगी- भजनलाल

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हैदराबाद में प्रवासी राजस्थान मीट में भाग लिया

जयपुर, 26 सितंबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हैदराबाद में आयोजित प्रवासी राजस्थानी मीट में कहा कि दुनियाभर में रहने वाले प्रवासी

- **मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष से 10 दिसम्बर को जयपुर में प्रवासी राजस्थान दिवस का आयोजन किया जायेगा। प्रवासी राजस्थानियों के सामाजिक और व्यावसायिक प्रभावों को मजबूती देने के लिए एक विशेष विभाग गठित किया जायेगा।**

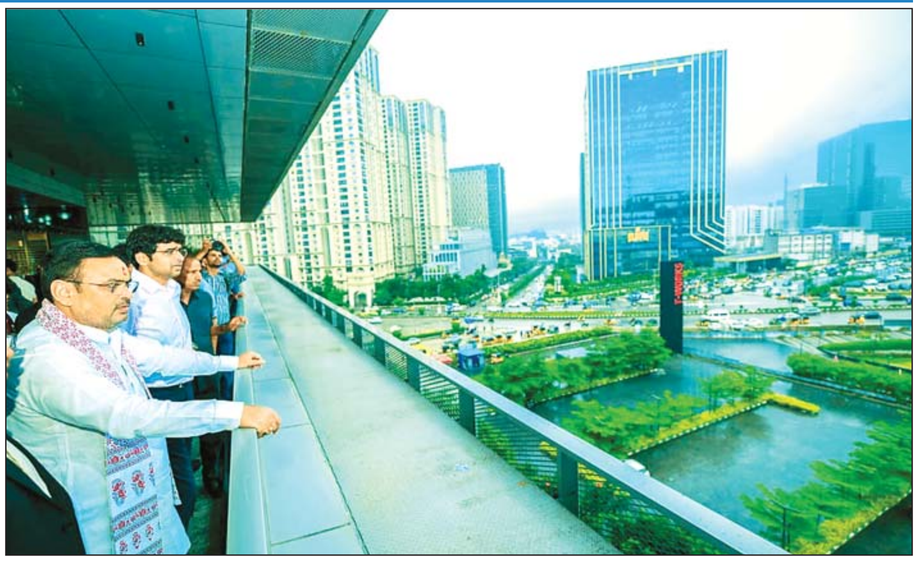

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को हैदराबाद में हाईटेक सिटी और आई टी हब का दौरा किया।

राजस्थानी जहां भी जाते हैं, वहाँ, अपनी संस्कृति और संस्कारों से राजस्थानी मिट्टी की खुशबू फैलाते हैं। उन्होंने प्रदेश में निवेश कर 'विकसित राजस्थान' के निर्माण में सहभागी बनने के लिए प्रवासी राजस्थानी का आव्हान किया।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रवासी राजस्थानियों को आमंत्रित करते हुए कहा कि 10 दिसंबर को जयपुर में प्रथम ''प्रवासी राजस्थानी दिवस'' आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन हर वर्ष किया जाएगा और इस अवसर पर हर साल ''प्रवासी राजस्थानी सम्मान'' भी दिया जाएगा। उन्होंने यह भी घोषणा की कि प्रवासी राजस्थानियों के सामाजिक और व्यावसायिक प्रयासों को मजबूती देने के लिए, एक विशेष विभाग गठित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रवासी राजस्थानियों की समस्याओं के समाधान के लिए हर जिले में अतिरिक्त जिला कलक्टर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। साथ ही,राजस्थान फाउंडेशन को सशक्त किया गया है। पिछले एक वर्ष में 14 नए चैप्टर खोले गए हैं और कुल 26 चैप्टर अब सक्रिय हैं।

दुनिया के न्यूयॉर्क, लंदन, रियाद जैसे प्रमुख शहरों में फाउंडेशन के चैप्टर सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए न्यूनतम निवेश की सीमा 100 करोड़ रुपये से घटाकर 50 करोड़, तथा रिप्स-2024 में 10 करोड़ कर दी गई है।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रवासी राजस्थानियों द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों की सराहना की और कई उद्यिमयों को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर राजस्थान फाउंडेशन की सदस्यता की शुरुआत भी की गई। कार्यक्रम में उद्योग राज्यमंत्री के के बिश्नोई, राजस्थान फाउंडेशन आयुक्त मनीषा अरोड़ा, प्रवासी समुदाय के अनेक प्रतिनिधि व उद्यमी उपस्थित थे।

दशकों से अमेरिका...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

भी टैरिफ में बदलाव किया गया है। कुछ बड़ी दवा कंपनियाँ अपनी निवेश योजनाओं को यूरोप और ब्रिटेन में स्थित अपने पुराने ठिकानों से हटाकर अमेरिका की ओर ज्यादा केन्द्रित करने की कोशिश कर रही हैं।

हालांकि भारत नए टैरिफ से प्रभावित हो सकता है, लेकिन इससे यूरोपीय और ब्रिटिश दवा कंपनियों के हितों को गहरा धक्का लग सकता है। उदाहरण के लिए, लंबे समय से स्थापित दवा कंपनी ग्लैक्सो स्मिथक्लाइन बीचम अपने कुछ प्रस्तावित निवेश ब्रिटेन से हटाकर अमेरिका में स्थानांतरित कर रही है, ताकि टैरिफ के असर को कम किया जा सके।

दवाओं के अलावा, राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश के तहत, भारी ट्रकों और कुछ फ़र्नीचर उत्पादों, जैसे किचन कैबिनेट्स और बाथरूम फिटिंग्स पर भी टैरिफ लगाया गया है। फ़र्नीचर बनाने वाली अग्रणी स्वीडिश कंपनी को भी इन नए शुल्कों का सामना करना पड़ेगा।

ट्रंप ने दवाओं...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कर रही है, लेकिन अब यह आशंका है कि भारत से निर्यात होने वाली कॉम्प्लेक्स जेनेरिक और स्पेशलिटी मेडिसिन्स भी इस दायरे में आ सकती हैं। हालांकि भारत की कई बड़ी कंपनियों के अमेरिका में पहले से उत्पादन केन्द्र मौजूद हैं, फिर भी इस नीति से उनका मुनाफा प्रभावित हो सकता है। अमेरिकी बाजार में पहले से ही कम मुनाफे पर काम कर रहीं भारतीय कंपनियों को इन शुल्कों को झेलना मुश्किल लग सकता है और अंततः इसकी लागत उपभोक्ताओं या बीमा कंपनियों पर डाल सकती हैं।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि अमेरिकी उपभोक्ता कम कीमत वाली भारतीय जेनेरिक दवाओं पर निर्भर हैं। अगर इन पर भी शुल्क लागू हुआ, तो दवाओं की कीमतें बढ़ेंगी महंगाई बढ़ेगी और संभवतः दवा की कमी भी हो सकती है ट्रंप पहले ही भारतीय उत्पादों पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा चुके हैं, जिसमें रूस से तेल खरीद जारी रखने के लिए 25 प्रतिशत पेनल्टी टैक्स भी शामिल है।

इलाहाबाद ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आज फैसला सुनाया गया। राहुल गांधी ने वाराणसी के स्पेशल जज, एमपी/एमएलए कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। उन्होने वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा निगरानी याचिका स्वीकार किए जाने को दी थी। उच्च न्यायालय से याचिका खारिज होने के बाद अब वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट में निगरानी याचिका पर आगे की सुनवाई होगी। पिछली 21 जुलाई को वाराणसी एमपी/एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के ख़िलाफ़ निगरानी याचिका को स्वीकार किया था जिसके खिलाफ राहुल गांधी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की शरण ली थी।

जस्टिस एस.पी. ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

फिलहाल जस्टिस एसपी शर्मा राजस्थान हाईकोर्ट में वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। जस्टिस शर्मा 26 सितंबर, 2026 को रिटायर होंगे।

आईटी मंत्री अश्विनी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

- **''स्वदेशी टैक'' को एक एडवान्टेज जरूर है, उनके समक्ष भारत का विशाल ''डॉमैस्टिक'' मार्केट है और उन्हें विदेशी ग्राहकों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।**
- **पर, यह भी सच है कि विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ दशकों से मार्केट में हैं तथा भारतीय ग्राहकों तक में उनके प्रति ब्राण्ड लॉयल्टी है।**

बड़ी संख्या में इंजीनियर, सॉफ़्टवेयर डेवलपर और बढ़ता हुआ स्टार्टअप इकोसिस्टम पहले से ही प्रतिस्पर्धी घरेलू समाधान बना रहे हैं। ज़ोहो और स्थानीय डिजिटल मैपिंग प्लेटफ़ॉर्म जैसे सॉफ़्टवेयर और सेवाओं के विकल्प यह साबित करते हैं कि देश व्यावहारिक विकल्प पेश करने में सक्षम है। विशाल घरेलू बाज़ार के साथ ये ताकतें तुरंत निर्यात पर निर्भर हुए स्थानीय नवाचार को बड़ा बनाने का अवसर देती हैं। संभावनाओं के बावजूद कई बाधाएँ हैं। कई घरेलू तकनीकी उत्पाद फीचर्स, भरोसेमंदी और उपयोगकर्ता अनुभव के मामले में अंतर्राष्ट्रीय उत्पादों से पीछे हैं, जिससे उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लिए बदलाव मुश्किल हो जाता है। हार्डवेयर और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स में गहरी संरचनात्मक समस्याएँ हैं, क्योंकि भारत अभी भी आयातित पुर्ज़ों और सीमित हाई-एंड विनिर्माण ढाँचे पर निर्भर है। आपूर्ति श्रृंखला की कमी, असंगत इंटरनेट कनेक्टिविटी और ग्रामीण ढाँचे की कमियाँ अपनाने की प्रक्रिया को और जटिल बनाती हैं। अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा भी दबाव बढ़ाती है। भारत को न केवल बराबरी करनी है बल्कि पहले से स्थापित बहुराष्ट्रीय कंपनियों से मुकाबला भी करना है, जिसके लिए लगातार रिसर्च और डवलपमैंट में निवेश करना नई प्रतिभा को जोड़ना व आधुनिक सुविधाओं का निर्माण करना होगा। उपभोक्ता व्यवहार- जिसे ब्रांड वफ़ादारी, कीमत की संवेदनशीलता और गुणवत्ता की धारणा प्रभावित करती है-भी एक चुनौती है। अगर मजबूत बौद्धिक संपदा सुरक्षा और वैश्विक मानकों का पालन नहीं किया गया तो घरेलू विकल्पों के लिए भरोसा पाना कठिन होगा। स्वदेशी टैक पहल में बदलाव लाने की ताकत है।

मनमोहन सिंह के...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के नेता राहुल गांधी तथा अन्य कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। खरगे ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को उनकी जयंती पर नमन करते हुए कहा कि देश में उन्होंने जो आर्थिक सुधार शुरु किए उनके कारण राष्ट्र आज तेजी से आर्थिक प्रगति कर रहा है।

रॉनल्ड रीगन के...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आज की वैश्विक आर्थिक उथल-पुथल के समय में भारत के लिए घरेलू मांग को बढ़ावा देना ज़रूरी है। अमेरिका में टैरिफ बाधाओं की वजह से भारत के निर्यात का बड़ा भाग देश के भीतर ही अटका हुआ है, बजाय उन बाज़ारों में पहुँचने के, जहाँ के लिए इन्हें बनाया गया था। इन सामानों की बिक्री तभी होगी, जब घरेलू मांग मज़बूत हो, ताकि सामान मैनुफैक्चर करने वालों पर अतिरिक्त माल का बोझ न पड़े।

- **पर, यह भी सच है कि एक त्योहार का सीजन पर्याप्त नहीं है, देश की इकॉनमी को पार लगाने के लिए। जनता की डिमांड में कुछ स्थायित्व होना जरूरी है। अर्थशास्त्री यह भी आशा कर रहे हैं कि एक सफल सीज़न में जो ''डॉमेस्टिक डिमांड'' जागृत हुई है, उसकी लत लगेगी जनता को और भारत की इकॉनमी का चक्का चल निकलेगा, जैसा रीगन के समय हुआ था।**

इसीलिए प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे त्योहार मनाएँ, खर्च करें, जिससे अर्थव्यवस्था को बढ़ी हुई मांग की मजबूत खुराक मिल सके। निश्चित रूप से इस समय जीएसटी दरों में की गई कटौती के कारण कीमतें घटने पर खरीदारों की तरफ से प्रतिक्रिया उत्साहपूर्ण होगी। उदाहरण के तौर पर, मोटर वाहनों की ऑन रोड कीमतों में कटौती हुई है। इसके परिणामस्वरुप, कार और दोपहिया वाहनों की कीमतों में भारी कमी आई है। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि ऑटोमोबाइल निर्माताओं की बिक्री ज्यादा होगी।

कम कीमत वाले सामानों, जैसे बिस्कुट पैकेट से लेकर दवाइयों तक, दरों में कटौती से भी मांग में उछाल आएगा और बिक्री में तेजी होगी। हालाँकि केवल एक त्योहार के मौसम की बिक्री लंबी अवधि में बड़ा असर नहीं डाल सकती। मांग में लगातार और स्थायी बढ़ोतरी के लिए मज़बूत आधार होना चाहिए और यह भी ज़रूरी है कि मांग एक ऊँचे स्तर पर जाकर स्थिर हो।

अर्थशास्त्र केवल त्योहारी सीज़न की बिक्री और खुशगवार माहौल से नहीं चलता। इन प्रोत्साहनों को लंबे समय तक सफल बनाने के लिए मांग में वृद्धि को लंबे समय तक बनाए रखना होगा। यह काम केवल एक बार की दर कटौती से कहीं ज्यादा कठिन काम है।

एक आशाजनक संकेत यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से अपनी आंतरिक खपत पर आधारित है और पूरी तरह से निर्यात पर ज़्यादा निर्भर नहीं है। इसलिए मौजूदा स्थिति में घरेलू खपत में बढ़ोतरी अगर लंबे समय तक जारी रही, तो यह विकास का इंजन बन सकती है। भारतीय अर्थव्यवस्था की अपनी आंतरिक गति को देखते हुए यह उम्मीद की जा सकती है कि यह अर्थव्यवस्था को उच्च विकास के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए पर्याप्त प्रारंभिक बल देगी। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि सरकार ऐसे कदम न उठाए, जो अर्थव्यवस्था के इस स्वाभाविक विकास प्रक्रिया में रुकावट डालें।

पाकिस्तान ने फिर...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप को सुविधानुसार पाकिस्तान की आधिकारिक यात्रा पर आने का भी सौहार्दपूर्ण निमंत्रण दिया।''संघर्षविराम के पहले दिन से ही भारत यह कहता आया है कि यह पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य अधिकारी ने ही अपने भारतीय समकक्ष से संपर्क कर शत्रुता समाप्त करने और शांति स्थापित करने के लिये सम्पर्क किया था।

जब यह संदेश आया, तब तक भारत पहले ही पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में कई प्रमुख आतंकी ठिकानों को तबाह कर चुका था, जिनमें सैन्य लक्ष्य जैसे हैंगर, रडार, एंटी-एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म और एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं महंगा एडब्ल्यूएसीएस (एयरबोर्न वॉर्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम) विमान शामिल थे, जो ज़मीन पर मौजूद था। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा है कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने उन्हें फोन कर कहा था कि ''पाकिस्तानी बातचीत के लिए तैयार हैं,'' जिसके बाद पाकिस्तान के डायरेक्टर-जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन्स ने भारत से संपर्क किया।

जयशंकर ने हाल ही में संसद में ''ऑपरेशन सिंदूर'' पर हुई बहस के दौरान कहा था, ''22 अप्रैल (पहलगाम आतंकी हमला) और 17 जून (संघर्षविराम की घोषणा की तिथि) के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और ट्रंप के बीच कोई बात नहीं हुई।'' 2016 के उरी सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 की बालाकोट एयरस्ट्राइक या अन्य पूर्व सैन्य अभियानों, जो ''स्केल'' तथा ''स्कोप'' के मामले में सीमित थे, तुलना में, ऑपरेशन सिंदूर तकनीकी रूप से कहीं अधिक उन्नत, विस्तृत और भारत द्वारा अब तक की गई।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2009/28296 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600